

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3607
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3607. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन कृषि जिंसों की सूची का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए सरकार द्वारा खरीफ मौसम के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की घोषणा की जाती है;
- (ख) उन कृषि जिंसों की सूची का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए सरकार द्वारा खरीफ मौसम के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन अभियान चलाया जाता है;
- (ग) खरीफ मौसम के अंतर्गत सभी कृषि जिंसों के लिए मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए नामित की गई सरकार की नोडल एजेंसियों की सूची का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार की मूल्य समर्थन प्रचालन नीति किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों पर खरीदी गई कृषि जिंसों के प्रसंस्करण की अनुमति देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री राम नाथ ठाकुर)

(क): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों जिसमें 14 खरीफ फसलें यथा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूँग, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल और कपास शामिल हैं, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

(ख) से (घ): सरकार, किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब कभी भी दलहनों और तिलहनों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहनों और तिलहनों की खरीद की जाती है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा कपास की खरीद भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।
